

ट्रांसक्रिप्ट

पावर फाइनेंस कारपोरेशन का सम्मेलन हेतु आमंत्रण

कार्यक्रम की अवधि: 1 घंटा 23 मिनट 8 सेकेंड

प्रस्तावना:

संचालक:

सभी उपस्थित महिलाओं और महानुभावों को नमस्कार। हम 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की चौथी तिमाही के परिणामों की घोषणा के अवसर पर आयोजित निवेशकों के सम्मेलन में पावर फाइनेंस कारपोरेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट जनसंपर्क से निनी सिंह। मैं यहाँ उपस्थित गणमान्य लोगों से आप सभी का परिचय कराना चाहती हूँ। डायस पर हमारे बीच सर्वप्रथम श्री सतनाम सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि.; उनके दांयी ओर श्री एम के गोयल, निदेशक, आईडी एवं ए, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि.; श्री गोयल के दायी ओर श्री आर नागराजन, निदेशक, वित्त एवं वित्तीय संचालन। श्री नारायण के दायी ओर श्री मुरली मोहनाराव, स्वतंत्र निदेशक। श्री सिंह के बांयी ओर श्री राजीव शर्मा, निदेशक परियोजनाएं। श्री शर्मा के बायीं ओर श्री एस सी गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक और इनके बांयी ओर श्री रविन्द्र एच ढोलकिया उपस्थित हैं। अब मैं श्री सतनाम सिंह को माइक सौंपते हुए डायस पर आने और कंपनी से संबंधित जानकारी देने का अनुरोध करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद ।

श्री सतनाम सिंह: आप सभी को नमस्कार। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि शाम हो गयी है। यदि संचालिका ने सांयकाल की घोषणा की थी परंतु मुझे लगता है कि अभी दोपहर है। हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने और यहाँ उपस्थित होने तथा निष्पादन पर सरसरी नजर डालने के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम इस 16 जुलाई को हम 24 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे और कंपनी 25वें वर्ष में प्रवेश करेगी। इसप्रकार यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस वर्ष में भी प्रवेश कर लिया है। हमने कंपनी की 25वीं सालगिरह भव्य तरीके से मनाने के लिए योजना बनायी है। आपको ज्ञात है कि भारत सरकार निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दे रही है इसलिए हम 25वें वर्ष में ऐसे कुछ कार्यकलाप करने वाले हैं। किसी भी तरह इस वर्ष की शुरुआत से लेकर अभी तक 2 अथवा 3 अवसर ऐसे रहे जिनकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। इनमें से

एक तो वह है कि जब हमने ऋण उधार देना प्रारंभ किया था उस समय हमने भारतीय विद्युत क्षेत्र के साथ शुरुआत की जबकि भारतीय विद्युत क्षेत्र को धन उधार देने वाले वित्तीय संस्थानों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। हमें यह विशेष जिम्मेदारी अव्यवहार्य क्षेत्र में व्यवहार्यता सृजन के लिए दी गयी थी। हमने उस जिम्मेदारी को वखूबी और सफलता पूर्वक निभाया है। वर्तमान में जैसा कि आपको ज्ञात है ज्यादा से ज्यादा बैंक विद्युत क्षेत्र को धन उधार देना चाहते हैं।

हमने भारत सरकार की बहुत सी नीतियों के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 9वीं पंच वर्षीय योजना – यह त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत नोडल एजेंसी के भीतर तेजी से क्षमता अभिवृद्धि के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। 10वीं योजना – एपीडीआरपी योजना का उद्देश्य वितरण संबंधी हानियों को कम करना था। हमने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में जो हानियां 38 से 39 प्रतिशत के बीच थीं उनमें 6 से 8 प्रतिशत की कमी लाते हुए लगभग 33 प्रतिशत तक लाया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारी क्षमता की मांग और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिए दो पहल प्रारंभ की गयीं। इस बार एक बार फिर हमें नोडल एजेंसी का दायित्व सौंपा गया। हमने पहले ही ऐसी 4 परियोजनाएं सफल बोली दाताओं को सफलतापूर्वक हस्तांतरित की हैं, 5वीं परियोजना प्रगति पर है और ऐसी बहुत सी परियोजनाएं भविष्य में भी मिलने की संभावनाएं हैं। एपीडीआरपी योजना का उद्देश्य वितरण संबंधी हानियों को कम करना है अथवा तकनीकी एटीएनसी हानियों को इस ढंग से पुनः तैयार करना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उसे निष्पादन उन्मुख बनाया जा सके। एक बार फिर इस योजना के लिए भी हमें नोडल एजेंसी का दायित्व सौंपा गया है। इस योजना का उद्देश्य वितरण संबंधी हानियों को उनके वर्तमान स्तर 30 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक कम करना है। इस योजना के अंतर्गत 30 हजार से अधिक आबादी वाले सभी कस्बों को शामिल किया जाता है। एक अन्य योजना भी है जिसे सरकार शीघ्र ही कार्यान्वित करने वाली है। इस योजना की घोषणा बजट सत्र के दौरान की गयी। इस योजना का नाम राष्ट्रीय

विद्युत निधि रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे कस्बों को शामिल किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 30 हजार से कम है। इस योजना के लिए भी हमें नोडल एजेंसी बनाए जाने की संभावना है। सरकार ने इस योजना के लिए बजट में कुछ निधि उपलब्ध करायी है परंतु इसकी औपचारिक घोषणा अभी की जानी है। इस प्रकार हमने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

वित्त वर्ष के निष्पादन पर बात करें तो इस दौरान हमने कुछ चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। मैं आपके साथ उन चुनौतियों और हमने किस तरह उनका सामना किया इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पहली चुनौती जिस पर निवेशकों ने भी मुझसे कई बार चर्चा की, यह थी कि पिछले वर्ष जुलाई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह प्रतिबंध अधिरोपित किया गया था कि पीएफसी राज्य और केंद्रीय क्षेत्र को धन उधार देने में रोक लगाए क्योंकि उनका मानना था कि हमने पहले से ही काफी कारोबार कर लिया है। हमने इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया और विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इस बात पर सहमत किया कि यह वर्तमान की आवश्यकता है और उन्होंने मार्च 2012 तक इन शर्तों की स्वीकार्यता से हमें छूट प्रदान की है। और यहां तक कि मार्च 2012 के बाद भी यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इन शर्तों (मानकों) को लागू किया जाएगा। मार्च 2012 के पश्चात हमसे यह अपेक्षा है और वास्तव में न केवल भारतीय रिजर्व बैंक ने हमसे यह जानकारी चाही है बल्कि निजी क्षेत्र के सभी वित्तीय संस्थानों से एक ऐसा रोड मैप प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया है जिस पर वे आम सहमति के लिए चर्चा करेंगे। अतः हो सकता है कि उस समय राज्य, केन्द्र क्षेत्र के संदर्भ में इस छूट की सीमा को आगे बढ़ाया जाए। इस चर्चा के एक भाग के रूप में हमें भी एक लाभ हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों द्वारा गारंटीत ऋणों के लिए जोखिम भार को 100 प्रतिशत से 20 प्रतिशत घटाने के लिए सहमति व्यक्त की है। जिसका हमारी पूंजीगत पर्याप्तता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अगली चुनौती भारी मात्रा में क्षमता अभिवृद्धि से संबंधित थी। इसके लिए दो प्रयास शुरू किए गए । 1. अल्ट्रा मेगा पॉवर परियोजनाएं। प्रारंभ में यह विचार किया गया था कि केवल 9 अल्ट्रा मेगा पॉवर परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ा कर 14 कर दी गयी है तथा इनका कार्य प्रगति पर है। हमने इस संबंध में पहले भी आपको जानकारी दी है कि इनमें से 4 परियोजनाओं का अधिनिर्णय सफलतापूर्वक कर दिया गया है। कुछ आंशिक संशोधनों के साथ मौजूदा दिशा निर्देशों के आधार पर दो अन्य परियोजनाओं के अधिनिर्णय की हमें अनुमति दी गयी है। एक परियोजना के लिए हमने आरएफक्यू पहले ही 15 मार्च को जारी कर दिये हैं और इन्हें प्रस्तुत करने के लिए 3 मई की तारीख निर्धारित की है। हो सकता है कि इसकी जानकारी आपको भी हो। अन्य परियोजना उड़ीसा के बेडाबहल में प्रारंभ की जानी है। जहां केवल एक ही पूर्व अहर्ता शेष है और वह भूमि के लिए धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना से संबंधित है। जैसे ही यह कार्य हो जाता है, इस परियोजना के लिए भी आरएफक्यू जारी करने के लिए हम तैयार हैं। अन्य अल्ट्रा मेगा पॉवर परियोजनाओं के लिए आरएफक्यू संशोधित दिशा निर्देशों के आधार पर चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाएंगे। अभी ये दिशा निर्देश मंत्रियों के कुछ अधिकार प्राप्त समूहों के विचाराधीन है। भारी क्षमता अभिवृद्धि और उसके लिए संगत धनराशि की आवश्यकता संबंधी चुनौती का भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंशिक समाधान कर दिया गया है और इस संबंध में हमारा यह मत है कि भारतीय रिजर्व बैंक पूर्व में एनबीएफसी को केवल दो वर्गों में ही विभाजित करने वाला था; या तो ऋण कंपनियां अथवा परिसम्पत्ति वित्तपोषण कंपनियां। हमें वर्तमान में ऋण कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था और हमारे एक्सपोजर संबंधी मानक ऋण कंपनियों की संपूर्ण शासन व्यवस्था के अनुसार थे अथवा हमारे लिए भी वैसे ही मानक लागू हैं। परंतु अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी की एक और नयी श्रेणी एनबीएफसी अवसंरचना वित्तीय कंपनियां बना दी है। जिसके लिए कुछ निश्चित खंड जोड़े गए हैं और इनके कुछ अच्छे पहलू और कुछ अलग आवश्यकताएं भी हैं। सकारात्मक पक्ष यह है कि एनबीएफसी

आईएफसी कंपनी के एक्सपोजर मानक किसी एकल ऋण ग्राही के साथ साथ सामूहिक ऋण ग्राहकों के लिए ऋण कंपनी की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक हैं। हमने आज अपने बोर्ड के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यह पहल करने का निश्चय किया है कि हमें ऐसी श्रेणी में रखा जाए जो भारतीय विद्युत क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता को वास्तविक रूप से पूरा करने की दृष्टि से उपयुक्त हो क्योंकि इस क्षेत्र की आवश्यकता अधिक है। इस संरचना के साथ 15 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता है। ऋण कंपनी पीएसयू के रूप में हमें सामान्य पूंजीगत पर्याप्तता की शर्तों से छूट प्रदान की गयी थी। हमसे 10 प्रतिशत के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए कहा गया, परंतु यदि हमारा पुनः वर्गीकरण एनबीएफसी आईएफसी के रूप में किया जाता है तो हमें 15 प्रतिशत की पूंजीगत पर्याप्तता बनाए रखनी होगी और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि वर्तमान स्तर क्या है। पिछली बार जब मैंने निवेशकों को संबोधित किया था तो मैंने यह उल्लेख किया था कि पूंजीगत पर्याप्तता 17.2 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है। परंतु राज्य सरकारों द्वारा गारंटीत ऋणों के भारित जोखिम में 100 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के परिवर्तन के साथ दिसंबर में इसे बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया गया था। परंतु मार्च के अंत में इसका स्तर 19.25 प्रतिशत रहा। इस प्रकार 10 प्रतिशत आवश्यकता के सापेक्ष अंतर काफी कम हो गया है क्योंकि अब यह आवश्यकता महज 15 प्रतिशत है। इस प्रकार अंतर केवल 4.25 प्रतिशत का है और इस तथ्य पर विचार करें कि हमने 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है तो अगले वर्ष की समाप्ति तक हमारी पूंजीगत पर्याप्तता 17.5 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो जाएगी। इस प्रकार हम इसके 15 प्रतिशत तक कम होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हमें पूंजीगत बाजार के साथ तालमेल रखना होगा, हो सकता है इसमें एक वर्ष का भी समय लग जाए; परंतु यह सभी बातें रिजर्व बैंक द्वारा हमें इस श्रेणी में वर्गीकृत करने पर आधारित होंगी। हमने चालू वित्त वर्ष में अपनी वृद्धि दर को अपेक्षित स्तर पर बनाए रखा है, अतः पूंजीगत समता हमारे लिए आवश्यक हो सकती है। मैं नहीं जानता कि यह हमारे निवेशकों के लिए शुभ

समाचार होगा अथवा अशुभ परंतु मेरा यह मानना है कि यह निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। वे हमसे लगातार पूछते रहे हैं कि हमारी फ्लोटिंग दरें बहुत ही कम 10.22 प्रतिशत हैं और बड़े निवेशक विशेष रूप से यह आग्रह करते रहे हैं कि फ्लोटिंग दरों में वृद्धि की जानी चाहिए। परंतु चूंकि हमारे पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध थी, अतः हमने इस ओर प्रयास नहीं किए चूंकि एनबीएफसी आइएफसी की इस प्रक्रिया के माध्यम से कारोबार के विस्तार का स्पष्ट लाभ दिखायी देता है, अतः हम उस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए योजना बना रहे हैं और इस तरह हम इक्विटी पूंजी भी बढ़ा सकते हैं। -----

हमने भारतीय रिजर्व बैंक से यह भी अनुरोध किया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपयुक्त दर पर धन उधार देने का प्रस्ताव दे रहा है, अतः वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 27000 करोड़ की कुल आवश्यकता में से एक मिलियन डॉलर उधार लेने की हमें अनुमति प्रदान की जाए और हम इस आशय से एक सम्मेलन आयोजित करेंगे कि क्या हमें एमटीएन कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए अथवा समेकित ऋण या वर्न संबंधी मुद्दों या ऐसे ही अन्य विकल्पों को चुनना चाहिए।

आरएपीडीआरपी स्कीम, जिसका उद्देश्य वितरण हानियों को कम करना है, भलिभाँति जारी है। आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि स्टेट ऑफ दी आर्ट सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आधारभूत डेटा की स्थापना हेतु शामिल किए जाने वाले कुल 1400 कस्बों में से उत्तर पूर्व के कुछ कस्बों को छोड़ कर ज्यादातर के लिए हमने ऋण मंजूर कर दिए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत अगला चरण प्रणालियों को अद्यतन करने वाली परियोजनाओं के लिए ऋण मंजूर करने से संबंधित है जिससे कि वितरण संबंधी हानियों को वास्तविक रूप से कम किया जा सके। अतः हमने यह पिछले वित्त वर्ष में ही प्रारंभ कर दिया था और संभवतः वर्तमान वित्त वर्ष में कुछ कस्बों को शामिल किया जाएगा और शेष बचे कस्बों को आगामी वित्त वर्ष में शामिल किए जाने की योजना है और इस प्रकार हम आगामी वित्त वर्ष तक इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। इस योजना के परिणाम दो वर्ष की समय अवधि में

सामने आने लगेंगे। मंजूरी से 18 माह के भीतर आधारभूत डेटा तैयार करने से यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वर्तमान में हानि का स्तर क्या है क्योंकि अभी तो आंकड़ों और उन्हें कम करने का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। वास्तव में भारतीय विद्युत क्षेत्र में स्टेट ऑफ दी आर्ट सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में नहीं सोचा गया। अभी आप देखें तो चाहे वह इन्फोसिस हो या विप्रो अथवा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी किसी भी कंपनी का नाम हो, वे सभी कंपनियां विद्युत क्षेत्र में वितरण संबंधी हानियों को कम करने के लिए प्रयासरत हैं और इसीलिए मुझे विश्वास है कि इसका भारतीय विद्युत बाजार पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

बहुत से निवेशकों और स्टैकहोल्डर द्वारा उठाया गया अन्य मुद्दा यह था कि एक ओर जहाँ देश में भारी मात्रा में क्षमता अभिवृद्धि की जा रही है वहीं दूसरी ओर क्या हमारे पास विद्युत पारेषण के लिए पर्याप्त पारेषण प्रणाली उपलब्ध है। हाँ, जहाँ तक अल्ट्रा ट्रांसमिशन अथवा बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों का संबंध है तो हमें ऐसी तीन लाइनों के अधिनिर्णय का कार्य प्रतियोगी बोली आधार पर सौंपे जाने के लिए दिया गया है। एक परियोजना का कार्य गत वर्ष हमने स्टर्लाइट को सौंप दिया था और उसके एवज में 15 करोड़ रुपए का शुल्क अर्जित किया था। अन्य दो परियोजनाओं के लिए आरएफक्यू जारी कर दिए गए हैं और मुझे आप सभी को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि कल उनमें से एक आरएफक्यू बोली को खोला गया। इनके संबंध में बहुत से रुझान और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। पश्चिमी क्षेत्र जबलपुर लाइन के लिए आरएफक्यू के जबाव में 33 कंपनियों ने अपनी दरें उद्धृत की हैं। अन्य आरएफक्यू के लिए 30 तारीख को बोली खोली जाएगी। मुझे आशा है कि उस लाइन के लिए भी कंपनियों के इसी तरह के रुझान प्राप्त होंगे। हमें अधिनिर्णीत की गयी लाइनों की जानकारी इस प्रकार है। कुछ लाइनों का काम आरईसी के पास है अंतर्राज्यीय लाइनों का कार्य पावर ग्रिड कर रहा है। यहां तक कि कुछ राज्यों द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राज्यीय लाइनों का कार्य

चालू और आगामी वित्त वर्ष में किए जाने की संभावना है । यह फीडबैक मुझे विद्युत मंत्रालय से प्राप्त हुआ है।

विद्युत की उपलब्धता और आवश्यकतानुसार इसका संचलन एक बड़ा प्रश्न है। इस दिशा में भी हम विद्युत विनिमय में भागीदारी निभाते हुए अपनी एक भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि हम भारत के विद्युत विनिमय और राष्ट्रीय विद्युत विनिमय दोनों में भागीदार हैं और उपर्युक्त दोनों कार्यक्रमों में हमारी इक्विटी भागीदारी भी है। पिछले वित्त वर्ष में किए गए कुछ प्रयासों के अंतर्गत हमने वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए एक अलग विंग की स्थापना की थी, जिसे हमने 'पश्चिम एकीकरण परियोजना' का नाम दिया है अर्थात् इसके अंतर्गत कोयला खानों, विद्युत उपस्कर विनिर्माण और विद्युत परियोजनाओं अथवा गैस परिवहन के लिए समर्पित गैस स्टेशनों का वित्त पोषण किया जाता है। वास्तव में इसके हमें बहुत ही सकारात्मक रुझान प्राप्त हुए हैं और हमने एक ऋण स्वीकृत कर दिया है तथा चार पांच प्रस्तावों पर कार्रवाही जारी है। हमने केएसके सूर्या फोटोवोल्टिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को 250 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। यद्यपि यह 2000 करोड़ रुपए की परियोजना है और हम बहुत ही सतर्क ढंग से इस परियोजना का वित्त पोषण कर रहे हैं, फिर भी यह हमारे लिए नया क्षेत्र है और हम विद्युत क्षेत्र में अपने अनुभव के अनुरूप 20 से 25 प्रतिशत तक की राशि ऋण रूप में नहीं दे रहे हैं। हम सीमित तरीके से राशि उधार दे रहे हैं, जैसे जैसे हमें इस क्षेत्र-का अनुभव होता जा रहा है, 250 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। हम इस क्षेत्र का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और अपने कारोबार के लिए नए क्षेत्र तलाश कर रहे हैं। वायु चालित यंत्रों के विनिर्माण, कोयला ब्लॉक के विकास आदि के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सौर ऊर्जा विनिर्माण के क्षेत्र में भी कुछ परियोजनाएं हैं।

हमारे बहुत से निवेशकों ने हमसे यह पूछा है कि हम केवल भारत तक ही क्यों सीमित हैं, हम अपने कारोबार का विस्तार विदेशों तक फैलाने के लिए

प्रयास क्यों नहीं करते हैं। इसलिए हम भूटान और नेपाल में भी कारोबार की कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं। नेपाल से हमें एक ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन जैसी एक कंपनी स्थापित करने पर विचार करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने यह महसूस किया है कि पीएफसी मॉडल भारतीय विद्युत क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सफल रहा है और उनका मानना है कि यदि नेपाल में भी इसी तरह का संगठन स्थापित हो जाता है तो नेपाल के विद्युत क्षेत्र का भी कल्याण हो जाएगा। अतः उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या हम उसका हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए हम संभावनाओं की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भारतीय कंपनियां वहां अपनी परियोजनाएं स्थापित कर रहीं हैं। उन कंपनियों ने भी वित्त पोषण के लिए हमें प्रस्ताव दिया है क्योंकि नेपाल में उत्पादित विद्युत की काफी बड़ी मात्रा भारतीय उपभोक्ताओं को थोक में बेचे जाने की संभावना है। समझौता I, II, और III पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ परमाणु ऊर्जा को गति मिली है और इसमें लगातार वृद्धि हुई है। उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए हम न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन के लगातार संपर्क में हैं। वास्तव में हम कल उनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले थे, परंतु कुछ आकस्मिक व्यवस्थाओं के कारण उन्हें यह कार्यक्रम अभी रद्द करना पड़ा है। इस प्रकार मैं जिस बारे में चर्चा कर रहा हूं वह हमारे लिए एक नया अवसर है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन, जो कि परमाणु क्षमता अभिवृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, के साथ इस क्षेत्र में भी बड़े कारोबार की संभावना है।

ऊर्जा सक्षमता ब्यूरो और भारत सरकार द्वारा काफी जोर दिये जाने के पर आप देखेंगे कि अब उपस्करों पर ऊर्जा दक्षता की स्टार रेटिंग दी जाने लगी है। और लोग अब ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं कि 'कौन सा उपस्कर?', 'कौन सा टीवी?', 'कौन सा रेफ्रिजरेटर?', और 'कौन सी वाशिंग मशीन?' बिजली की

बचत करती हैं और इसी के अनुरूप वे इन उपस्करों का प्रयोग करते हैं। अतः हम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड में एक इक्वीटी भागीदार हैं जो हमें परामर्श के संदर्भ में सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान करने अथवा संभवतः ऊर्जा सेवा कंपनियों के सृजन में सहयोग प्रदान करेगा।

इक्वीटी फंडिंग एक ऐसा अन्य क्षेत्र है जिसके बारे में निवेशक और अन्य निदेशक हमसे प्रश्न पूछते रहे हैं। मैंने पूर्व में भी बताया था कि पिछले बार हमने एक उत्पाद- नई अथवा विस्तार परियोजनाओं की इक्वीटी में निवेश के प्रावधान के साथ स्थापित परियोजनाओं के सापेक्ष ऋण प्रारंभ किया था। उस उत्पाद के बारे में हमें बेहतर रुझान प्राप्त हुए हैं परंतु हम उस क्षेत्र में अधिक कारोबार नहीं कर सके हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य क्षेत्र के लिए हमारी एक्सपोजर संबंधी शर्तों पर प्रतिबंध लगा दिया है और हमें केवल राज्य क्षेत्र के लिए ही लाया गया था तथा उस अवधि के दौरान हम पर यह प्रतिबंध लगा हुआ था। अब वह प्रतिबंध हटा लिया गया है अतः इस क्षेत्र में भी बड़े कारोबार की संभावना है।

हमने राज्य क्षेत्र के लिए गंगटोक में और आईपीपी के लिए अमृतसर में ऋणग्राहियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। दोनों बैठकों के दौरान इस उत्पाद के उत्कृष्ट रुझान प्राप्त हुए। वास्तव में आईपीपी इस उत्पाद की जिज्ञासा के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि आईपीपी के लिए भी इस उत्पाद को बहुत शीघ्र शुरू किया जाए। हमारे पास इक्वीटी के अधिग्रहण हेतु कुछ प्रत्यक्ष प्रस्ताव भी हैं। कुछ समय पहले समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित की गयी थी कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन 5 प्रतिशत से 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष इक्वीटी अवक्षेपित कर रहा है, हाँ यह सही है परंतु हम यह कार्य केवल तभी कर सकते हैं जब हमारा बोर्ड इस विषय पर हमारे निवेशकों और स्टोक होल्डरों की एक बैठक आयोजित करता है। यह विचाराधीन है , इसके बारे में कुछ प्रश्न भी उठाए गए हैं। इस क्षेत्र में भी काफी बड़े कारोबार की संभावना है। गत वर्ष मैंने एक उदघोषणा की थी कि हम दा सहायक कंपनियां स्थापित करेंगे। अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम संविदाकारों के

समूह को ऋण उधार देने के क्षेत्र में एक कंपनी सृजित करने के लिए तैयार हैं। इसका औचित्य एक समान है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरोत्तर क्षमता अभिवृद्धि में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में काफी अधिक है। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में 28 प्रतिशत और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 63 प्रतिशत थी। जैसा आपको ज्ञात है कि निजी परियोजनाओं के लिए कोई भी संस्थान संपूर्ण ऋण राशि उधार नहीं देता है। अतः ऐसी स्थिति में समूह गठित किए जाने की आवश्यकता है। हमें इस क्षेत्र में भी कारोबार की संभावना प्रतीत होती है और इस क्षेत्र में बेहतर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम पीएफसी के एक भाग के रूप में अधिक कार्य नहीं कर सकते हैं। हम पिछले दो वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से यह कार्य करते रहे हैं और संविदाकारों के समूहों को ऋण उधार देने संबंधी परियोजनाओं के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करते रहे हैं। परंतु हम यह महसूस करते हैं कि यदि हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा और इसके लिए कम से कम कार्यपालक निदेशक स्तर पर अपने लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है ताकि इस कारोबार को स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा सके। इसी प्रकार हम शीघ्र ही यह नयी कंपनी बनाने वाले हैं। इसी प्रकार की कंपनी हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी गठित कर सकते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में भी कारोबार बढ़ रहा है, परंतु इसमें अभी समय लगेगा।

जहां तक परामर्श सेवाओं का प्रश्न है तो इसके लिए हमने पीएफसी के 100 प्रतिशत नियंत्रणाधीन एक सहायक कंपनी बनायी हुई है। हम इस क्षेत्र में अपने लाभ को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। गत वर्ष हमने इस क्षेत्र से 22 करोड़ रुपए की धनराशि अर्जित की है। हमारे पास 106 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएँ हैं। खास बात यह है कि इस दिशा में हमारी सेवाओं और प्रयासों को मान्यता दी जा रही है और अन्य मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दस्तावेजों के साथ साथ मानकों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का कार्य

सौंपा है। ऐसा इसलिए है कि उन्हें लगता है कि हमने पारंपरिक ऊर्जा, दस्तावेज तैयार करने, संविदाओं के अधिनिर्णय आदि के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, इसीलिए उन्होंने हमें यह कार्य सौंपा है। हम इस दिशा में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। अधिग्रहण सलाहकार सेवा एक ऐसा अन्य क्षेत्र है जिसका उल्लेख मैंने पिछली बार किया था और यह संभावना व्यक्त की थी कि जब बाजार में निजी क्षेत्र की बहुत सी कंपनियां आ जाएंगी तो इस कारोबार को गति मिलेगी और इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उनमें से कुछ कंपनियां अधिग्रहण का मार्ग चुनेंगी और इस प्रकार हमने यह महसूस किया कि चूंकि हम भारतीय विद्युत बाजार में एक बड़ी कंपनी हैं, अतः हमें लगभग सभी परियोजनाओं के बारे में पूरी जानकारी है और हम उन कंपनियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं जो अधिग्रहण के क्षेत्र में अपना कारोबार प्रारंभ करती हैं। इस प्रकार यह यूनिट भी पहले से कार्य कर रही है, संभावनाओं की तलाश कर रही है, इतना ही नहीं कि हमारे पास बड़ी संख्या में अनुरोध लंबित हैं बल्कि हम उन पर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। कंपनी की संपूर्ण दक्षता में सुधार के लिए कुछ अन्य विकास कार्य भी किए गए हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आपके साथ साझा करना चाहिए। हमारे पास अब स्वयं का ईआरपी है; प्रचालनात्मक दक्षता बढ़ाने और निर्णय के लिए डेटा की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्तमान वित्त वर्ष से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। हमने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संशोधित मान (स्केल), निष्पादन से संबद्ध वेतन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो पूर्व में प्रयुक्त दिशा निर्देशों से अलग हैं। यह सभी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रोत्साहन के कुछ प्रतिशत के रूप में होगी और शेष राशि निष्पादन पर आधारित होगी। इस प्रकार जहां कहीं भी आप निष्पादन के लिए कुछ प्रोत्साहन का प्रावधान करते हैं तो आप सुरक्षित ढंग से यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका निष्पादन पहले की तुलना में बेहतर होगा क्योंकि लोग उस कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए प्रेरित रहते हैं। हम कंपनी के सभी

प्रचालनों के लिए आईएसओ 9001/2008 के प्रमाणपत्र से अभिप्रमाणित हैं। हमने यह प्रक्रिया दो से ढाई अथवा तीन वर्ष पहले प्रारंभ की थी। सबसे पहले हमने इसे अलग प्रभाग के रूप में शुरू किया था, इसके लिए परियोजना प्रभाग, वित्त तत्पश्चात संस्थागत विकास और अब संपूर्ण कंपनी के लिए हमने यह प्रक्रिया शुरू की है।

मैंने कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि धारा 4क कंपनी होने के नाते हमें कुछ निश्चित कर छूट की पात्रता मिली हुयी थी। इस प्रकार की छूट (ब्रेक) अशोध्य और संदेहास्पद कर्ज के लिए आरक्षित निधि सृजित करने के लिए दी गयी थी। हम इस आरक्षित निधि के लिए हर वर्ष अपने निबल लाभ की 5 प्रतिशत राशि जमा करते रहे हैं। परंतु पिछले 24 वर्ष में हमने शून्य अशोध्य कर्ज बट्टे खाते में डाला है और हमारी गैर निष्पादन परिसंपत्तियां उद्योग जगत में सबसे कम अर्थात 0.02 प्रतिशत हैं। इसलिए हम यह सोचते हैं कि आरक्षित निधि का यह आंकड़ा काफी अधिक है और इस मद में तुलनपत्र में 800 करोड़ की राशि दर्शायी गयी है। हमने यह आह्वान किया है कि हम इस आरक्षित निधि को अपने सामान्य कारोबार में नहीं लगायेंगे, इसमें हमने लगभग 16 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच राशि जमा की है। हम इस आरक्षित निधि का निवेश चरणबद्ध ढंग से रीयल स्टेट में करेंगे जिससे कंपनी के लिए आगे अधिक धनराशि अर्जित की जा सके।

गत वर्ष हमारे प्रयासों की सराहना सभी फोरमों, सार्वजनिक और निजी पर की गयी। मैं आपके साथ कुछ पुरस्कारों की चर्चा करूंगा जो हमें पिछले वित्तीय वर्ष में मिले। वर्ष 2007 508 में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए प्रधानमंत्री से समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच उत्कृष्टता के लिए एनबीएफसी श्रेणी में भारतीय गौरव पुरस्कार, नवोन्मेषी वित्त पोषण के लिए भारतीय विद्युत पुरस्कार, गैर विनिर्माण श्रेणी में हैवी वेट नवरत्न पीएसयू और खासतौर पर दलाल स्ट्रीट से गैर विनिर्माण श्रेणी में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले नवरत्न पीएसयू का पुरस्कार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुझे आप सभी को यह जानकारी देते हुए हर्ष है कि

हम विद्युत मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी हैं। हमने पिछले वित्त वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में उल्लेखित मानदण्डों को पूरा किया है।

अब मैं आंकड़ों की बात प्रारंभ करता हूँ; मैं तिमाही वार तुलनात्मक विवरण पर चर्चा करूँगा और फिर उसके पश्चात आपके समक्ष वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत करूँगा। हमारी कुल आय में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। मैं करोड़ रुपए में आंकड़े उद्धृत नहीं करूँगा क्योंकि ये हमेशा आपको उपलब्ध हो सकते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है हमारे प्रेजेन्टेशन को हमारी वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है, आप वह देख सकते; परंतु मैं अभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूँगा तत्पश्चात प्रेजेन्टेशन भी दूँगा। वार्षिक आधार पर हमारी कुल आय 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जैसा आपको ज्ञात है कि पिछले वर्ष हमने इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की दलील के आधार पर आस्थगित कर देयता के लिए समायोजन किया। इसके परिणामस्वरूप हमने 483 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जो कि पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित था क्योंकि उस दौरान कोई भी समायोजन नहीं किया गया था। अब यदि उस लाभ को निकाल लिया जाता है तो वर्ष 2009 की चौथी तिमाही की तुलना में वर्ष 2010 की चौथी तिमाही में हमारा लाभ 45 प्रतिशत है और वार्षिक लाभ में वृद्धि 58 प्रतिशत है। निश्चित ही हम राष्ट्रीय आधार पर विदेशी विनिमय से होने वाली हानि लाभ के बारे में चर्चा करते रहे हैं, इसके अलावा इस दौरान हमें कुछ राशि आयकर वापसी के रूप में भी प्राप्त हुई है, यदि इन सभी राशियों का समायोजन किया जाता है तो तुलनात्मक रूप से हमारे पीएटी में 26 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है और वार्षिक आधार पर पीएटी 32 प्रतिशत है। तिमाही के लिए लब्धि कम रही है इसमें 39 आधार बिंदुओं की कमी हुयी और इस वर्ष के लिए 17 आधार बिंदुओं की गिरावट दर्ज की गयी क्योंकि हम बाजार के आधार पर अपनी उधारी की दरों में समायोजन करते रहे। परंतु अधिक कमी निधियों की लागत में हुई और पिछली तिमाही में इसमें 46 आधार बिंदुओं और समग्र आधार पर 57

समग्र बिंदुओं की वृद्धि की गयी। इसके परिणामस्वरूप तिमाही ने हमारा विस्तार 7 आधार बिंदुओं का रहा और वार्षिक आधार पर हमने 40 आधार बिंदुओं की वृद्धि की। महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे हमारी वृद्धि दर क्या हो सकती है? गत वर्ष परिसम्पत्ति वृद्धि 24 प्रतिशत रही। यह पूर्व में व्यक्त की गयी हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। खासतौर से बकाया मंजूरीयों की राशि 141800 करोड़ रुपए है। जिस अवधि में इन मंजूरीयों को पूरा किया जाना है वह लगभग 3 से 4 वर्ष की बीच है। इस प्रकार आप यह कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ तक कि आज तक की बकाया मंजूरीयों के बावजूद भी भविष्य में अपनी वृद्धि दर बनाए रखने में सक्षम होंगे। यदि हम भविष्य में ऋण मंजूर करते हैं और नए क्षेत्रों से अतिरिक्त कारोबार मिलता है तो हमारा निष्पादन अपेक्षाकृत अधिक बेहतर होगा।

इस सभी के परिमाणस्वरूप कंपनी के बुक मूल्य में वृद्धि हुई है और यह 94 से बढ़कर 110 हो गया है परंतु यदि हम इस डीटीएल के लिए समायोजन करते हैं तो यह एक वर्ष की अवधि में वास्तविक रूप से 90 से 110 रहेगा। इसी प्रकार मिलने वाला रिटर्न भी 20 प्रतिशत की रेंज में है परंतु यदि समायोजन किए जाते हैं तो आप देखेंगे कि औसत निबल मूल्य में भी थोड़ी सी वृद्धि होगी। मैं सोचता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री श्रीधर को आमंत्रित करूँगा जो विस्तार से अपनी प्रस्तुति देंगे और तत्पश्चात प्रश्नोत्तर का दौर चलेगा।

श्रीधर: अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद। सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। अब हम वर्ष 2009 10 की अंतिम तिमाही के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन के निष्पादन संबंधी विवरणों पर आधारित एक छोटा सा प्रेजेन्टेशन देखेंगे और तत्पश्चात आपके समक्ष वर्ष 2009 10 के परिमाणों की घोषणा की जाएगी। पहली कुछ स्लाइडों में पीएफसी के बारे में और पीएफसी के कारोबार के बारे में जानकारी दी गयी है, जिनकी जानकारी संभवतः आप सभी को पहले से ही है। इसलिये मैं इस जानकारी को पढ़ लिया गया मान लूँगा, परंतु मैं इस बात पर अवश्य जोर देना चाहूँगा कि पीएफसी घरेलू और

अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग लगातार बनाए रखने में सफल रहा है। आईसीआरए और सीआरआईएसआईएल ने हमें 'एएए' और फिर मूडी, एस एण्ड पी और एफआईटीसीएच जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने हमें संप्रभु रेटिंग प्रदान की है। हमने पिछले दस वर्ष से इन रेटिंग को बनाए रखा है। वर्ष 2009 10 में हमने तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना सफल बोलीदाता रिवाइंस पावर लिमिटेड को हस्तांतरित की है और अपनी खाता बही में 15 करोड़ रुपए की आय शुल्क के रूप में अर्जित की है। इसी वर्ष में हमने ईस्ट नॉर्थ इंटरकनेक्शन कंपनी लिमिटेड, यूएमपीपी लाइन में एक पारेषण परियोजना का सफलतापूर्वक अधिनिर्णय सफल बोलीदाता स्टर्लाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड को किया है और हमारी सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 15 करोड़ रुपए की आय शुल्क के रूप में अर्जित की है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को पिछले वर्ष आईएसओ 9001:2008 से अभिप्रमाणित किया गया है। खासबात यह है कि संपूर्ण कंपनी के लिए यह अभिप्रमाणन किया गया है।

31 मार्च, 2010 को हमारे पास 302 कर्मचारियों का कार्यबल उपलब्ध है, संवितरण 25 करोड़ प्रति कर्मचारी है और लाभ 7.80 करोड़ रुपए प्रति कर्मचारी है। गतवर्ष हमें दलाल स्ट्रीट जरनल से भी एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार हमें प्रति कर्मचारी सर्वोच्च लाभ अर्जित करनेवाले सर्वश्रेष्ठ पीएसयू के रूप में प्रदान किया गया है। उस समय प्रति कर्मचारी हमारा लाभ 6.2 करोड़ रुपए था और अब हमने अपने रिकार्ड में और सुधार किया है। पिछले 5 वर्ष के लिए पीएफसी की वृद्धि सांख्यिकी की बात करें तो इसमें पिछले 5 वर्ष के दौरान वार्षिक वृद्धि दर में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है: मंजूरी में 29 प्रतिशत, संवितरण में 22 प्रतिशत, ऋण परिसम्पत्तियों में 22 प्रतिशत निबल मूल्य में 16 प्रतिशत कुल आय में 22 प्रतिशत पीएटी में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। हमने 4 रुपए प्रति शेयर की दर से वर्ष 2008 9 में 459 करोड़ रुपए के लाभांश का संवितरण किया है और वर्ष

2009 10 में 3 रुपए प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश वितरित किया है।

अब मैं वर्ष 2009 10 की उपलब्धियों के बारे में बात करूंगा। वर्ष 2009 10 में निबल लाभ 2355 करोड़ रुपए रहा जबकि गत वर्ष यह 1970 करोड़ रुपए था। इस प्रकार इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई और तुलनात्मक लाभ 32 प्रतिशत बढ़ गया। औसत परिसम्पत्तियों के प्रचालन लाभ में 18 आधार बिंदुओं की बढ़त हुई और यह 3.62 प्रतिशत से बढ़कर 3.80 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2009 10 में कुल आय 8074 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार इसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष 2009 10 में निबल ब्याज आय 2932 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार इसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष 2009 10 में संवितरण 25808 करोड़ रुपए था। इस प्रकार इसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। मंजूरी की राशि 65466 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। 31 मार्च 2010 को ऋण परिसम्पत्तियों की राशि 79856 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार इसमें पिछले एक वर्ष में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। कंपनी का निबल मूल्य 12618 करोड़ रुपए रहा। इस प्रकार इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ष 2009 10 में तुलनात्मक लाभ, अर्जित लाभ 2355 करोड़ रुपए था जबकि गत वर्ष यह 1970 करोड़ रुपए था। इस प्रकार इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। 843 करोड़ रुपए की विशेष आरक्षित निधि पर डीटीएल के कारण गत वर्ष बड़ी मात्रा में डीटीएल का प्रत्यावर्तन किया गया, यदि हम उस प्रभाव को नगण्य कर देते हैं तो उस स्थिति में लाभ में 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी जा सकेगी। इसके अलावा आयकर रिफंड के मद में हमारे पास एकमुश्त क्रेडिट प्लस माइनस, विनिमय से होने वाले लाभ हानि का विकल्प उपलब्ध था और यदि हम इन मदों का समायोजन करते हैं तो वर्ष 2009 10 में हमारा लाभ पिछले वर्ष 1605 करोड़ रुपए की तुलना में 2113 करोड़ रुपए होगा और इस प्रकार इसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि होगी। तिमाही परिणामों की घोषणा करने से पहले पिछली तिमाही का परिणामी लाभ गत

वर्ष में 1005 करोड़ रुपए की तुलना में 599 करोड़ रुपए रहा और इस प्रकार इसमें 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। परंतु हमने न केवल पूर्ववर्ती वर्षों के डीटीएल का प्रत्यावर्तन किया है बल्कि दिसम्बर 2008 तक प्राप्त डीटीएल का भी प्रत्यावर्तन किया है। इस प्रकार यह 593 करोड़ रुपए रहा। यदि हम इस प्रकार को नगण्य कर देते हैं तो लाभ में 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होगी। पूर्ववर्ती अवधि में 412 करोड़ रुपए की तुलना में गत वर्ष 599 करोड़ रुपए का लाभ हुआ इस प्रकार इसमें 40 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 45 प्रतिशत का लाभ रिपोर्ट किया गया। आयकर रिफंड और हस्तांतरणीय लाभ हानियों के मद में प्लस माइनस का समायोजन करने से पिछली तिमाही में हमारा तुलनात्मक लाभ पूर्व में 426 करोड़ रुपए की तुलना में 538 करोड़ रुपए रहा और इस प्रकार इसमें 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

लाभ हानि खाता: वर्ष 2009 10 में ब्याज से होने वाली आय गत वर्ष 6396 करोड़ रुपए की तुलना में 7860 करोड़ रुपए रहा। इस प्रकार इसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। ब्याज व्यय 4937 करोड़ रुपए था और उसमें 19 प्रतिशत की धीमी गति से वृद्धि दर्शायी गयी है इस प्रकार ब्याज से होने वाली आय में 23 प्रतिशत की वृद्धि तथा ब्याज व्यय में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार ब्याज से होने वाली निबल आय 2923 करोड़ रुपए है। इस प्रकार इसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गत वर्ष अन्य आय 88 करोड़ रुपए, प्रचालन लागत 107 करोड़ रुपए रहा। 2 करोड़ रुपए का राइट बैक प्रावधान किया गया था, इस प्रकार कर पूर्व लाभ और बाह्य मदों की राशि 2905 करोड़ रुपए रही और इसमें 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गयी। पिछले वर्ष 233 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष विनिमय से होने वाला लाभ और हानि 107 करोड़ रुपए रहा और इस प्रकार हमारे लाभ में सुधार हुआ। गत वर्ष 460 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 464 करोड़ रुपए का कर प्रावधान किया गया है। इस प्रकार इसमें 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। विशेष आरक्षित निधि के मद में निबल डीटीएल प्रत्यावर्तन के लिए भी

प्रावधान किया गया था कि गत वर्ष वास्तविक डीटीए पूर्व में 440 करोड़ रुपए की तुलना में 7 करोड़ रुपए रहा। इस प्रकार वर्ष 2009 10 में कर पूर्व लाभ 2355 करोड़ रुपए रहा जबकि गत वर्ष यह 1970 करोड़ रुपए था। इस प्रकार इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। यदि आप तिमाही परिणामों पर नजर डालेंगे तो ब्याज से होने वाली आय पूर्व में 1767 करोड़ रुपए की तुलना में 2083 करोड़ रुपए है। इस प्रकार इसमें 18 प्रतिशत और व्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। अतः ब्याज से होने वाली निबल आय में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। पूर्व में 632 करोड़ रुपए की तुलना में कर पूर्व लाभ और असाधारण मद की राशि 707 करोड़ रुपए रही और इस प्रकार इसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। अंत में कर पूर्व लाभ पूर्व में 1005 करोड़ रुपए की तुलना में 599 करोड़ रुपए रहा। मैंने यह बात पहले ही स्पष्ट की है कि डीटीएल प्रत्यावर्तन में समायोजन के पश्चात पिछली तिमाही में कोई गिरावट नहीं हुई है, बल्कि पिछली तिमाही में लाभ में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अलग अलग आइटमों की बात करें तो मैं कहूँगा कि पूर्ववर्ती अवधि में 67 करोड़ रुपए की तुलना में गत वर्ष अन्य आय 88 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार इसमें 31 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। यहां मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि हम ईबीआईटीए शुल्क से होने वाली आय की बुकिंग स्वीकृत राशि के 1 प्रतिशत के समतुल्य कर रहे थे, हमने गत वर्ष 17 करोड़ रुपए और 31 दिसंबर तक 9 माह की अवधि में 26 करोड़ रुपए बुक किए हैं। परंतु भारत सरकार ने अब एक अलग रणनीति अपनाई है, सरकार अब हमें शुल्क के रूप में आय का कुछ निश्चित अंश देने की बात कर रही है और कुछ अंश हमारे द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं में होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति स्वरूप किया जाएगा जो हम एपीडीआरपी योजना के क्रियान्वयन और संवितरण हेतु प्रदान करते हैं। इस व्यवस्था पर अभी बातचीत जारी है। इस व्यवस्था के संबंध में अंतिम निर्णय न लिए जाने के कारण हमने गत वर्ष बुक की गई 17 करोड़ रुपए

की आय और इस वर्ष 9 माह की अवधि में बुक की गई 26 करोड़ रूपए की राशि को प्रत्यावर्तित किया है। इस प्रकार, यदि हम एपीडीआरपी से होने वाली आय को हटा देंगे, तो गत वर्ष अर्थात वर्ष 2009 10 में अन्य आय 105 करोड़ रूपए होगी जबकि पूर्ववर्ती अवधि में यह 50 करोड़ रूपए थी। इस प्रकार इस मद में होने वाली आय लगभग दोगुनी है। यदि हम तिमाही अवधि को हटा देते हैं, तो एपीडीआरपी से इतर आय, शुल्क से होने वाली आय और अन्य आय वर्ष 2008 09 में 7 करोड़ रूपए थी जबकि वर्ष 2009 10 में यह 33 करोड़ रूपए है। इस प्रकार इसमें चार गुना वृद्धि हुई है। पूर्ववर्ती अवधि में 91 करोड़ रूपए की तुलना में गत वर्ष प्रचालन लागत 107 करोड़ रूपए थी। इस प्रकार, इसमें 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वेतन संशोधन के आधार पर हमारी कंपनी में भी वेतन संशोधन किया गया। इस प्रकार, ग्रेच्युटी, छुट्टी, नगदीकरण, अधिवर्षिता निधियों आदि जैसी वास्तविक मूल्यांकनों के आधार पर इन प्रावधानों में भी वृद्धि की गई। इस प्रकार, हमारी लागत में 107 करोड़ रूपए तक की वृद्धि हुई है। यदि आप चौथी तिमाही बनाम चौथी तिमाही की प्रचालन लागत पर नजर डालते हैं तो 27 करोड़ रूपए की तुलना में प्रचालन लागत 40 करोड़ रूपए थी। इसमें 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार अब प्रावधान संशोधित मान के अनुसार किए जाते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि प्रचालन लागत में वृद्धि आने वाले वर्षों में इतनी अधिक नहीं होगी। पूर्ववर्ती अवधि में 460 करोड़ रूपए की तुलना में गत वर्ष कर संबंधी प्रावधान 664 करोड़ रूपए था। इस प्रकार, इसमें 44 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यदि आप चौथी तिमाही के परिणामों पर नजर डालेंगे तो कर संबंधी प्रावधान वर्ष 2008 09 में 67 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2009 10 में 139 करोड़ रूपए था। इस प्रकार, इसमें 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस प्रकार, ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारे लिए उच्चतर कर अदायगी की स्थिति उत्पन्न हुई है, वर्ष 2008 09 में यह कर का मूल्यहास है, विदेशी परिसंपत्तियों और देनदारियों के परिवर्तन पर हमें विनिमय संबंधी लाभ हानि

हुई थी जिसके लिए हमें कर योग्य व्यय के रूप में अनुमति प्रदान नहीं की गई और न ही कर योग्य लाभ की गणना के समय इसे कर योग्य आय माना गया। परंतु गत वर्ष चौथी तिमाही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि जब विनिमय संबंधी लाभ, हानि को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है, तो कर की गणना करते समय राष्ट्रीय हानियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्ष 2008-09 की संपूर्ण अवधि में हमें लगभग 39 करोड़ रूपए का एक बड़ा कर लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में लगभग 91 करोड़ रूपए का लाभ मिला। इस प्रकार, यदि इसे नगण्य-कर-दिया-जाता है तो वर्ष 2008-09 और 2009-10 में कर अदायगी लगभग एक समान थी।

औसत परिसंपत्तियों पर रिटर्न के रूप में लाभ और हानि लेखा। ब्याज से होने वाली निबल आय वर्ष 2008-09 में 3.66 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009-10 में 3.82 प्रतिशत रही। इस प्रकार, इसमें 16 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई। अन्य आय से हमें गत वर्ष की तरह 11 आधार बिंदुओं का लाभ मिला। प्रचालन व्यय में गत वर्ष के 15 आधार बिंदुओं की तुलना में इस वर्ष 14 आधार बिंदुओं का लाभ मिला। इस प्रकार, प्रचालन लाभ वर्ष 2008-09 में 3.62 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009-10 में 3.80 प्रतिशत रहा। इस प्रकार, इसमें 18 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई। प्रावधान लगभग सपाट और नगण्य किए जाने योग्य हैं। विनिमय लाभ के कारण असाधारण मर्दों से इस वर्ष हमें 14 आधार बिंदु प्राप्त हुए और विनिमय हानि के कारण गत वर्ष हमें 38 आधार बिंदुओं को खोना पड़ा। करधान संबंधी प्रावधान के कारण इस वर्ष हमें 88 आधार बिंदु और गत वर्ष 75 आधार बिंदु का नुकसान हुआ। डीटीए के कारण डीटीएल के प्रावधान से इस वर्ष हमें 1 आधार बिंदु मिला और फिर डीटीएल के प्रत्यावर्तन के कारण गत वर्ष हमें 72 आधार बिंदु का लाभ मिला। इस प्रकार, कर पश्चात लाभ 3.08 प्रतिशत था। क्योंकि औसत परिसंपत्ति का अनुपात वर्ष 2008-09 में 3.21 प्रतिशत की तुलना में वर्ष

2009 10 में 3.08 प्रतिशत था अतः कर पश्चात लाभ में 13 आधार बिंदुओं की कमी दर्शायी गई है। परंतु वास्तविक रूप से यह कोई बड़ी गिरावट नहीं है। यदि आप डीटीएल प्रत्यावर्तन को नगण्य कर देते हैं, तो औसत परिसंपत्तियों पर रिटर्न वर्ष 2008 09 में 2.49 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009 10 में 3.07 प्रतिशत होगा। इस प्रकार, इसमें 58 आधार बिंदुओं की वृद्धि होगी।

हमारे तुलनपत्र का आकार 84,746 करोड़ रूपए था जिसमें से शेयरधारकों की निधि 16 प्रतिशत, उधारी 79 प्रतिशत, चालू परिसंपत्तियां 4 प्रतिशत और आस्थगित कर देयता, ब्याज सब्सिडी लगभग 1 प्रतिशत थे। परिसंपत्तियों को देखें तो तुलनपत्र का आकार 84,746 करोड़ रूपए था और वर्तमान परिसंपत्तियां 6 प्रतिशत थीं। निवेश और निर्धारित परिसंपत्तियां नगण्य अर्थात लगभग 0.1 प्रतिशत थीं।

अब महत्वपूर्ण संसूचकों की बात करते हैं। वर्ष 2009 10 में मंजूरीयों की राशि 65,466 करोड़ रूपए थी। इस प्रकार, इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निबल बकाया मंजूरी अर्थात संचित मंजूरीयों में से मार्च 2010 की समाप्ति पर संचित संवितरण राशि घटाने पर 1,41,813 करोड़ रूपए थी। इस प्रकार, इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2009 10 में 25,808 करोड़ रूपए का संवितरण किया गया। इसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऋण परिसंपत्तियां 79,856 करोड़ रूपए थीं। इसमें 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिसंपत्तियों पर लब्धि 10.92 प्रतिशत की तुलना में 10.75 प्रतिशत रही। इसमें 17 आधार बिंदुओं की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2008 09 में 8.71 प्रतिशत की तुलना में निधियों की लागत वर्ष 2009 10 में 8.14 प्रतिशत थी। इस प्रकार, इसमें 57 आधार बिंदुओं की गिरावट दर्ज की गई। इस प्रकार, ब्याज विस्तार में 40 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है और यह 2.21 प्रतिशत से बढ़कर 2.61 प्रतिशत हो गया है। निबल ब्याज मार्जिन 4 प्रतिशत रहा। इसमें 16 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई। औसत निबल मूल्य पर रिटर्न गत वर्ष के 20.23

प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 20.12 प्रतिशत रहा। इसमें 11 आधार बिंदुओं की गिरावट हुई। परंतु यदि आप डीटीएल प्रत्यावर्तन को नगण्य कर देते हैं तो औसत निबल मूल्य पर रिटर्न 15.27 प्रतिशत की तुलना में 19.97 प्रतिशत था। इस प्रकार, इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर्ज इक्विटी अनुपात 5.18 गुना था। इसमें 30 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई। प्रभावन क्षमता 6.53 गुना प्रतिशत थी। इसमें 22 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई। पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात 17.15 प्रतिशत की तुलना में 19.25 प्रतिशत था। हम पूंजीगत पर्याप्तता की गणना ऋण परिसंपत्तियों पर 100 प्रतिशत जोखिम भार डालते हुए करते रहे हैं। परंतु इस वर्ष अर्थात् 2009 10 की चौथी तिमाही में भारतीय रिजर्व बैंक ने हमें सरकार द्वारा गारंटीत ऋणों पर 20 प्रतिशत के कम जोखिम भार डालने की अनुमति प्रदान की है। इस प्रकार, हम उस कम जोखिम भार का प्रयोग कर रहे हैं और पूंजीगत पर्याप्तता की गणना 19.25 प्रतिशत की गई है। यदि आपने कम जोखिम भार का प्रयोग नहीं किया है, तो पूंजीगत पर्याप्तता गत वर्ष के 17.15 प्रतिशत की तुलना में 16.21 प्रतिशत होगी। परंतु यह केवल शैक्षणिक उद्देश्य है। हम पूंजीगत पर्याप्तता की गणना निम्नतर जोखिम भार के आधार पर ही करेंगे। अतः सभी उपयोगी उद्देश्यों के लिए 31 मार्च 2010 को पूंजीगत पर्याप्तता 19.25 प्रतिशत थी। प्रति शेयर अर्जन 20.52 रूपए अर्थात् प्रति शेयर 20 रूपए 52 पैसे था और प्रति शेयर बही मूल्य 109.49 रूपए था।

मंजूरियां। वर्ष 2009 10 में हमने 65,466 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की है, जिसमें से 67 प्रतिशत उत्पादन, 18 प्रतिशत पारेषण, ½ प्रतिशत वितरण, 10 प्रतिशत एपीडीआरपी और 6 प्रतिशत अन्य को की गई। यदि आप कुल स्वीकृत राशियों के सेक्टरवार आवंटन पर नजर डालेंगे तो 60 प्रतिशत राज्य क्षेत्र, 3 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र, 13 प्रतिशत संयुक्त क्षेत्र और 24 प्रतिशत निजी क्षेत्र को आवंटित की गई।

यदि आप शेयरों के संचलन पर नजर डालेंगे, तो पारेषण क्षेत्र में सुधार हुआ है और यह गत वर्ष 10 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 18 प्रतिशत हो गया है। राशिवार यह लगभग दोगुना हो गया है। जहां गत वर्ष यह 5800 करोड़ रूपए था वहीं इस वर्ष बढ़कर यह 11,620 करोड़ रूपए हो गया है। हमने राजकीय पारेषण कंपनियों को बड़ी राशि मंजूर की है।

सेक्टरवार नजर डालें तो केंद्रीय क्षेत्र की मंजूरी में गिरावट हुई है और यह गत वर्ष 32 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 3 प्रतिशत है। यह स्थिति मुख्य रूप से गत वर्ष हमारे द्वारा एनटीपीसी को 10,000, डीवीसी को 3,000 और निटको को 4,000 बड़े टिकिट मंजूर करने के कारण निर्मित हुई है। इस वर्ष हमने भारत बिजली रेल कंपनी को 2248 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की है। परंतु संयुक्त क्षेत्र के हिस्सेदारी में गत वर्ष 2 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमने संयुक्त क्षेत्र को कुछ बड़े टिकिट मंजूर किए हैं। राशिवार आवंटन के मामले में निजी क्षेत्र का आंकड़ा भी लगभग दोगुना हो गया है और यह गत वर्ष 7892 करोड़ रूपए से बढ़कर इस वर्ष 15786 करोड़ रूपए हो गया है।

संवितरण – वर्ष 2009 10 में हमने 25808 करोड़ रूपए का संवितरण किया है, जिसमें से 76 प्रतिशत उत्पादन, 4 प्रतिशत पारेषण, 2 प्रतिशत वितरण, 5 प्रतिशत एपीडीआरपी और 12 प्रतिशत अन्य को संवितरित किया गया। अनुशासनवार शेयरों का बहुत अधिक संचलन नहीं हुआ। परंतु क्षेत्रवार यह राज्य क्षेत्र को 62 प्रतिशत, केंद्रीय क्षेत्र को 25 प्रतिशत, संयुक्त क्षेत्र को 9 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को 4 प्रतिशत है। संचलनवार में यह कहूंगा कि राज्य क्षेत्र की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से घटकर 62 प्रतिशत हो गई है जबकि केंद्रीय क्षेत्र में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बड़े टिकिट मंजूरीयों को ऋण परिसंपत्तियों और संवितरण में परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया गया है।